श्रम कानूनों का उल्लंघन

1868. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन और कपड़ा उद्योगों द्वारा श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया और इससे कितने प्रतिशत श्रम-दिवसों की हानि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले पटसन और कपड़ा उद्योगपतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनको क्या सजा दी गयी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में कृषि श्रमिकों के लिये कल्याण योजना

1869. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :
श्रीमती जालदीबेन जेठाभाई पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषत: उत्तर प्रदेश और गुजरात के पिछड़े जिलों में कृषि श्रमिकों के लिये वर्ष 1992–93, 1993–94 और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक स्वीकृत की गई व्यापक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Rural Employment Scheme for Orissa

1870. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of PLANNING AND IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the different schemes being launched in the rural areas in Orissa to remove unemployment problem;

(b) the funds earmarked under those schemes during the last three years: and

(c) the details of the target set for the Eighth Five Year Plan and achievements made so far under those schemes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Employment in the States depends on the pace and pattern of development in the State, for which the State Government is mainly responsible. The Central Government supplements the efforts of the State Governments through Centrally Sponsored Schemes. The major poverty alleviation programmes being implemented in the rural areas of Orissa are: (i) the Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) the Jawahar Rozgar Yojna (JRY); and (iii) the Employment Assurance Scheme (EAS). While IRDP is a self-employment programme, the JRY and EAS are wage-employment programmes.